वर्ष 11 अंक 04 अक्टूबर-दिसम्बर 2025

जलागम दर्पण

जलागम प्रबन्ध निदेशालय द्वारा प्रकाशित त्रैमासिक पत्रिका

जलागम सचिव ने किया स्थलीय निरीक्षण ग्रामीणों से किया सीधा संवाद

श्री दिलीप जावलकर, सचिव जलागम व मुख्य परियोजना निदेशक ने दिनांक 10 अगस्त 2025 को पौड़ी जनपद के दुगड्डा ब्लॉक के जमरगड्डी गांव का दौरा किया। उन्होंने ग्रीन-एजी परियोजना के अंतर्गत किसानों एवं समुदाय के सहयोग से की जा रही गतिविधियों का स्थलीय निरीक्षण किया।

इस दौरान श्री दिलीप जावलकर ने ग्रामीण समुदायों से सीधे संवाद किया। ग्रामीणों द्वारा अवगत कराया गया कि इस वर्ष भारी वर्षा व लैंडस्लाइड से कई घरों को क्षति हुई है, जिसे जलागम सचिव द्वारा मौके पर जाकर देखा गया। स्थानीय लोगों ने उक्त गांव को जोड़ने वाले निर्माणाधीन पुल के कार्यों में तेजी लाने का अनुरोध किया तथा जंगली जानवरों के द्वारा कृषि खेती को नुकसान पहुंचाने की समस्या से भी अवगत कराया। जलागम सचिव द्वारा संबंधित अधिकारियों को इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए।

बैठक के दौरान ग्रीन-एजी परियोजना के अधिकारियों द्वारा अवगत कराया गया कि किस तरह यह परियोजना जलागम की अवधारणा से अलग लैंडस्कैप एप्रोच पर आधारित है।

इसमें कृषि को वैश्विक पर्यावरणीय उद्देश्य के साथ समेकित किया गया है। परियोजना के अति वरीयता में चयनित कुल 82 ग्रामों में मानव वन्य जीव संघर्ष, लेंटाना उन्मूलन, चैन लिंक घेर बाड़, स्थानीय प्रजातियों के बीजों/ नस्लों तथा फार्मर्स फील्ड स्कूल के माध्यम से कृषि को बढ़ावा देकर जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण के उद्देश्य से कार्य किए जा रहे हैं।

यह परियोजना ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी (GEF) के द्वारा वित्तपोषित एवं फूड एंड एग्रीकल्चर आर्गनाइजेशन (FAO) के सहयोग से क्रियान्वित की जा रही है। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी श्री गिरीश गुणवंत, संयुक्त निदेशक डा. एके डिमरी, उप वन संरक्षक तरुण एस. उप निदेशक डा. डीएस रावत, सहायक वन संरक्षक रजत कपिल आदि उपस्थित रहे।

पौड़ी के पश्चात सचिव जलागम ने अल्मोड़ा का दौरा किया। उन्होंने जिलाधिकारी कार्यालय के सभागार में जिले में संचालित विभिन्न विभागीय योजनाओं व कार्यक्रमों की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी योजनाओं का क्रियान्वयन समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण रूप से किया जाए, ताकि जनता को अधिकतम लाभ मिल सके।

परियोजना के जरिए ग्रामीणों की समस्याओं का होगा समाधान

श्री हिमांशु खुराना, अपर सचिव जलागम एवं परियोजना निदेशक, उत्तराखण्ड जलवायु अनुकूल बारानी कृषि परियोजना ने दिनांक 29.10.2025 को उत्तरकाशी जिले का दौरा किया। सर्वप्रथम उनके द्वारा डुण्डा यूनिट के ग्राम कुंसी में संसाधन एवं सामाजिक मानचित्र की रंगोली का अवलोकन किया गया।

उन्होंने ग्रामीणों के साथ सीधा संवाद करते हुये ग्राम पंचायत रेजीलिएंट प्लान में प्रस्तावित कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान बायो कम्पोस्ट व वर्मी कम्पोस्ट पिट देखे गये तथा ग्रामीणों की समस्याओं की जानकारी ली।

इसके पश्चात श्री हिमांशु खुराना ने ग्राम गेंवला में रबी सीजन में मटर एवं लहसुन की फसल प्रदर्शन का स्थलीय निरीक्षण किया तथा किसान हित समूह (एफआईजी) सदस्यों के द्वारा प्रयोग मे लाई जा रही मलचिंग शीट के फायदे के बारे में जानकारी ली। एफआईजी सदस्यों के द्वारा जैविक जीवामृत बनाने की विधि का लाइव डेमो भी प्रस्तुत किया गया।

इस मौके पर ग्राम प्रधान कुंसी व गेंवला एवं समस्त ग्रामीणों के साथ श्री हिमांशु खुराना ने परियोजना को लेकर बातचीत की। उन्होंने ग्रामीणों की समस्याओं का संज्ञान लेते हुए उप निदेशक, जलागम विभाग, उत्तरकाशी को निर्देश दिए कि परियोजना के अंतर्गत ऐसे कार्य कराए जाएं, जिससे अधिक से अधिक ग्रामीणों को लाभ मिल सके। इस दौरान विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ ही जलागम विभाग के अधिकारी तथा कर्मचारी उपस्थित रहे।

फूलों की खेती में होगी महिलाओं की विशेष भागीदारी

सुश्री कहकशाँ नसीम, परियोजना निदेशक जैफ-6 ने दिनांक 08.11.2025 को पौड़ी प्रभाग में संचालित ग्रीन-एजी जैफ-6 परियोजना क्षेत्र में यमकेश्वर ब्लॉक की ग्राम पंचायत कसान का दौरा किया तथा समीक्षा बैठक आयोजित की। भ्रमण के दौरान उन्होंने परियोजना के अंतर्गत हो रहे विभिन्न कार्यों, जैसे- चेन लिंक फेंसिंग, हल्दी उत्पादन, मृदा संरक्षण कार्य आदि का निरीक्षण किया।

उन्होंने गांव की महिला कृषकों से संवाद करते हुए आगामी फ्लोरिकल्चर (फूलों की खेती) गतिविधियों पर विशेष चर्चा की। गांव की महिलाओं ने फूल उत्पादन में गहरी रुचि दिखाई और इसे आजीविका सशक्तिकरण से जोड़ने के अपने विचार साझा किए।

सुश्री कहकशाँ नसीम ने महिलाओं के सुझावों और मांगों को ध्यानपूर्वक सुना तथा फूल उत्पादन गतिविधि को परियोजना के अंतर्गत प्रोत्साहित करने पर चर्चा की। साथ ही उन्होंने कहा कि आने वाले समय में फ्लोरिकल्चर उत्पादों की मार्केटिंग के लिए भी महिलाओं को प्रशिक्षित एवं समर्थित किया जाएगा ताकि वे अपनी उपज को बाजार में उचित मूल्य प्राप्त कर सकें। स्थानीय काश्तकारों से उनकी समस्याओं तथा परियोजना के माध्यम से उनके निराकरण के विषय में भी चर्चा की गई।

इसके साथ ही, उन्होंने कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन से भी परियोजना की प्रगति पर चर्चा की और फील्ड स्तर पर बेहतर समन्वय व समुदाय सहभागिता सुनिश्चित करने की बात रखी। इस दौरान परियोजना से जुड़े अन्य अधिकारी व कर्मचारी भी उपस्थित रहे।

निर्जलित पुष्प शिल्प पर आयोजित कार्यशाला में की भागीदारी

राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान, लखनऊ में 29 सितंबर से एक अक्टूबर तक तीनदिवसीय निर्जलित पुष्प शिल्प पर प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित की गई। इसमें उत्तराखंड से जलागम प्रबंध निदेशालय की ग्रीन एजी परियोजना टीम ने सहभागिता की। प्रशिक्षणार्थियों को निर्जलित फूलों के संरक्षण और उनके माध्यम से आकर्षक उत्पाद तैयार करने की तकनीक से अवगत कराया गया। विशेषज्ञों ने फूलों की गुणवत्ता बनाए रखते हुए उन्हें दीर्घकालीन उपयोग में लाने के विषय में जानकारी दी।

कार्यशाला में प्रशिक्षणार्थियों को रेज़िन आर्ट तकनीक की भी विस्तृत जानकारी दी गई। विशेषज्ञों ने बताया कि किस प्रकार रेज़िन का प्रयोग कर फूलों को संरक्षित करते हुए आकर्षक सजावटी सामग्री, प्राकृतिक रंगों का उपयोग कर ज्वेलरी, इयररिंग्स तथा अन्य उत्पाद तैयार किए जा सकते हैं। इस दिन केंद्रीय औषधीय एवं सगंध पौध संस्थान लखनऊ की शैक्षणिक यात्रा भी आयोजित की गई।

प्रशिक्षण का औपचारिक समापन राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान के निदेशक डा. अजीत कुमार शासनी की उपस्थिति में हुआ। समापन सत्र के दौरान सभी प्रतिभागियों को प्रमाणपत्र प्रदान किए गए। ग्रीन-एजी परियोजना टीम ने कन्नौज के सुगन्ध एवं सुरस विकास केन्द्र तथा मुन्नालाल एंड सन्स के हेरिटेज हाउस का भी शैक्षणिक भ्रमण किया। ये दोनों संस्थान प्राकृतिक सुगंध और इत्र निर्माण की प्राचीन कला को संरक्षित और प्रोत्साहित करने के लिए प्रसिद्ध हैं।

राज्य स्थापना की रजत जयंती के अवसर पर आयोजित किए गए विभिन्न कार्यक्रम

मीडिया कवरेज

10 दैनिक जागरण देहरादून, 9 अक्टूबर, 2025 उत्तराखंड

नदियों के पुनर्जीवन को 'एक जिला-एक नदी'

जलागम सचिव दिलीप जावलकर ने सारा की कार्यसमिति की बैठक में दिए निर्देश

जलागम सचिव दिलीप जावलकर ने बुधवार को सचिवालय में स्प्रिंग एंड रिवर रिज्युविनेशन आथारिटी की राज्य स्तरीय कार्यसमिति की बैठक ली • सूचि

इन योजनाओं को दी गई स्वीकृति

जिला	नदी	कार्यदायी संस्था
पौड़ी	इरगाड (पैडुल निसनी) स्यूलगाड (राठूली) व ह्यूनिल	लघु सिंचाई
नैनीताल	भलुगाड एक व दो	वन विभाग
चंपावत	कलसेन	लघु सिंचाई
पिथौरागढ़	घटीगाड व तितरगाड	वन विभाग

राज्य ब्यूरो, जागरण • देहरादून: उत्तराखंड में जलस्रोतों व नदियों के पुनर्जीवन के लिए अब 'एक जिला-एक नदी' की अवधारणा पर केंद्रित कार्ययोजना तैयार की जाएगी। जलागम सचिव एवं स्प्रिंग एंड रिवर रिज्युविनेशन अथारिटी (सारा) के मुख्य कार्यकारी अधिकारी दिलीप जावलकर ने सारा की राज्य स्तरीय कार्यसमिति की बैठक में यह निर्देश दिए। इस मौके पर पौड़ी, नैनीताल, चंपावत व पिथौरागढ़ जिलों की सात नदियों के लिए आठ नई कार्ययोजनाओं को स्वीकृति दी गई। इनकी कुल लागत 24.68 करोड़ है, जिसमें 18.61 करोड़ रुपये सारा से आवंटित किए जाएंगे।

सचिवालय स्थित वीर चंद्र सिंह गढ़वाली सभागार में हुई बैठक में जलागम सचिव जावलकर ने जल संरक्षण एवं नदी पुनर्जीवन से संबंधित कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिए कि प्रत्येक जिला अपनी एक प्रमुख या संकटग्रस्त नदी की पहचान कर उसके जलसमेट क्षेत्रों में जलस्रोतों के पुनर्जीवन व संचयन कार्यों को प्रभावी रूप से कराना सुनिश्चित करे। उन्होंने जिला पर गठित सारा समितियों की बैठकें कर इनमें पारित प्रस्तावों को आगामी राज्य स्तरीय बैठक में प्रस्तुत करने के लिए भी निर्देशित किया।

धारा-नौला संरक्षण समितियों का करें गठन : सचिव जावलकर ने जल संरक्षण के कार्यों में स्थानीय समुदायों की भागीदारी सुनिश्चित करने पर भी बल दिया। साथ ही इसके लिए ग्राम स्तर पर धारा-नौला संरक्षण समितियों का शीघ्र गठन कराने को कहा। यह समितियां स्थानीय स्तर पर निगरानी की जिम्मेदारी निभाएंगी। इसके लिए सारा से इन्हें वित्तीय व तकनीकी सहायता दी जाएगी।

ऐतिहासिक, सांस्कृतिक विरासत को संजोने पर बल: राज्य में स्थित पारंपरिक धारों व नौलों की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक विरासत को संजोते हुए इनके पुनर्जीवीकरण पर भी सचिव जलागम ने विशेष जोर दिया। उन्होंने स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन के दृष्टिगत पैराहाइड्रोलाजिस्टों की तैनाती करने, सभी कार्य क्षेत्रों में जल संरक्षण के लिए ईको फ्रेंडली संरचनाएं विकसित करने, जलस्रोतों व जल निकायों के पुनर्जीवन से जुड़े सभी विभागों के मध्य बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने, विभागों, शैक्षणिक व तकनीकी संस्थानों, जनप्रतिनिधियों और जनता को क्षमता विकास एवं कार्यशाला से जोड़ने और आरसीसी चेकडैम की वर्षाकाल के बाद की स्थिति का मूल्यांकन करने के निर्देश भी दिए।

सारा की अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी कहकशां नसीम ने एक करोड़ से अधिक लागत वाली आठ कार्ययोजनाओं पर प्रस्तुतीकरण दिया।

शिप्रा नदी किनारे चलाया सफाई अभियान

शिप्रा नदी की सफाई करते लोग

नैनीताल। राज्य की रजत जयंती के उपलक्ष्य में नदी उत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत सोमवार को भवाली की शिप्रा नदी के तटवर्ती क्षेत्रों में स्वच्छता अभियान चलाया गया।

यह अभियान सारा, नैनीताल एवं नगर पालिका परिषद, भवाली के सौजन्य से जिला प्रशासन, नैनीताल द्वारा आयोजित किया गया। उल्लेखनीय है कि सारा स्प्रिंग एण्ड रिवर रिज्युविनेशन ऑथोरिटी के अंतर्गत शिप्रा नदी को एक जनपद-एक नदी योजना के अंतर्गत भी अंगीकृत किया गया है। मुख्य विकास अधिकारी, नैनीताल अनामिका सिंह तथा जिला विकास अधिकारी, नैनीताल गोपाल गिरि गोस्वामी के दिशा निर्देशन में यह अभियान ग्यारहसेक्टरों में विभाजित कर सम्पन्न कराया गया, जिसमें विभिन्न विभागों के अधिकारियों को नोडल अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया। इस कार्यक्रम के समग्र नियोजन एवं निष्पादन कार्य हेतु उप निदेशक, जलागम डा. एसके उपाध्याय, मुख्य नोडल अधिकारी की भूमिका में रहे।

प्रात: 9 से अपरान्ह 2 बजे तक शिप्रा नदी, घोड़ाखाल रोड, भवाली मुख्य बाजार, रामगढ़ रोड, श्यामखेत चाय बागान, श्मशान घाट, रानिखेत रोड, भवाली, कैंची धाम, निगलाट, रातीघाट, रामगढ़ आदि स्थानों पर विशेष सफाई अभियान संचालित किये गये। इस अभियान में नगर पालिका, ग्राम पंचायतों, स्वजल, जल निगम, समाज कल्याण, शिक्षा, कृषि, उद्यान, पशुपालन, पर्यटन, जल संस्थान, लघु सिंचाई, ग्रामीण निर्माण, पूर्ति विभाग सहित अनेक विभागों की सक्रिय सहभागिता रही। स्थानीय जनप्रतिनिधियों, महिला मंगल दलों, स्वयं सहायता समूहों, आशा एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं तथा नागरिकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया।

ग्राम पंचायत स्तर पर धारा-नौला संरक्षण समितियों का गठन करें

सारा की बैठक में चंद्रभागा नदी के पुनर्जीवन के लिए 174.70 लाख स्वीकृत

अमर उजाला ब्यूरो

देहरादून। सचिव जलागम व स्प्रिंग एंड रिवर रिजुविनेशन अथॉरिटी (सारा) के मुख्य कार्यकारी अधिकारी दिलीप जावलकर ने कहा कि जल संरक्षण कार्यों में स्थानीय समुदायों की भागीदारी सुनिश्चित की जाए। साथ ही ग्राम पंचायत स्तर पर धारा-नौला संरक्षण समितियों का जल्द गठन किया जाए, जो स्थानीय स्तर पर निगरानी करेगी।

सचिव जावलकर ने स्प्रिंग एंड रिवर रिजुविनेशन अथॉरिटी की राज्य स्तरीय कार्यकारी समिति बैठक की। बैठक में जल संरक्षण और नदी पुनर्जीवन से जुड़ी कार्ययोजनाओं को स्वीकृति दी गई, जिनकी कुल लागत 382.26 लाख है। इसमें वर्षा आधारित नदियों के पुनर्जीवन की योजना के तहत चमोली जिले की चंद्रभागा नदी के लिए 174.70 लाख की परियोजना को भी हरी झंडी दी गई। इसके अलावा इसमें नैनीताल और ऊधमसिंह नगर के लिए भू-गर्भीय जलभृत रिचार्ज की 207.56 लाख की कार्ययोजना को भी स्वीकृति दी गई है।

धारों, नौलों के पुनर्जीवीकरण के लिए चिह्नीकरण के निर्देश

सचिव जावलकर ने पारंपरिक धारों व नौलों के पुनर्जीवीकरण के लिए तत्काल चिह्नीकरण करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही प्रदेश की रजत जयंती के अवसर पर आयोजित सभी जिलों के कार्यक्रमों का डाक्यूमेंटेशन जल्द शासन को भेजने को कहा। जल स्रोतों और नदी पुनर्जीवन से जुड़े सभी रेखीय विभागों को आपस में समन्वित रूप से काम करने को भी कहा।

जिला स्तर पर सारा की बैठक करें, प्रस्तावों को प्रस्तुत करें

सचिव जावलकर ने कहा कि जिला स्तर पर सारा समितियों की बैठकें कर प्रस्तावों को आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाए। वन डिस्ट्रिक्ट, वन रिवर के सिद्धांत पर तैयार की जा रही अपनी कार्ययोजनाओं में जलागम से जुड़े कार्यों को प्रमुखता से शामिल करें, जिससे अधिक से अधिक वर्षा के जल का संरक्षण किया जा सके। उन्होंने सारा से जुड़े कार्यदायी रेखीय विभागों की टेक्निकल टीमों को ट्रेनिंग देने के साथ ही स्थानीय स्तर पर पैराहाइड्रोलॉजिस्टों की ट्रेनिंग आयोजित करने का भी निर्देश दिया। परियोजनाओं में अधिकाधिक जनभागीदारी सुनिश्चित करने के लिए क्षमता विकास व कार्यशालाओं के आयोजन करने को कहा। बैठक में सारा की अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी कहकशां नसीम ने एक करोड़ से अधिक लागत की कार्ययोजनाओं का विस्तृत प्रस्तुतीकरण दिया। बैठक में वन, सिंचाई समेत अन्य विभाग के अधिकारी मौजूद थे।

जलागम सचिव ने सुनी किसानों की समस्याएं

- जमरगड्डी गांव में ग्रीन-एजी परियोजना के अंतर्गत किए जा रहे कार्यों का निरीक्षण किया
- ग्रामीणों ने गांव को जोड़ने वाले निर्माणाधीन पुलों के निर्माण कार्य में तेजी लाने की मांग की

जागरण संवाददाता, कोटद्वार: ग्रीन-एजी परियोजना के तहत शुक्रवार को जलागम सचिव दिलीप जावलकर ने दुगड्डा प्रखंड के अंतर्गत जमरगड्डी गांव का निरीक्षण किया। उन्होंने ग्रामीणों से संवाद कर उनकी समस्याएं सुनी।

शुक्रवार को जलागम प्रबंधन निदेशालय के सचिव दिलीप जावलकर ने जमरगड्डी गांव में ग्रीन-एजी परियोजना के अंतर्गत किए जा रहे कार्यों का निरीक्षण किया। साथ ही कृषि क्षेत्र में नवाचारों को देखा। उन्होंने ग्रामीण समुदायों से वार्ता भी की। ग्रामीणों को बताया कि ग्रीन-एजी परियोजना लैंडस्कैप एप्रोच पर आधारित है व कृषि को वैश्विक पर्यावरणीय उद्देश्य के साथ समेकित करती है।

परियोजना के अति वरीयता में चयनित 82 गांवों में मानव वन्य जीव संघर्ष, लैंटाना उन्मूलन, चैन लिंक घेर बाड़ बनाए जा रहे हैं। साथ ही स्थानीय प्रजातियों के बीजों/नस्लों व फार्मर फील्ड स्कूल के माध्यम से कृषि को बढ़ावा देकर जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण के उद्देश्य से क्रियान्वित की जा रही है। सचिव ने मुख्य विकास अधिकारी गिरीश गुणवंत व खंड विकास अधिकारी बीडी रतूड़ी को ग्रीन-एजी परियोजना में स्थानीय कृषक/समूहों की कृषि इनपुट्स की आपूर्ति व उनकी मांग को सम्मिलित करने हेतु निर्देश दिए गए।

उन्होंने भूस्खलन से कई घरों को इस वर्ष की वर्षा आपदा से क्षति का भी निरीक्षण किया। ग्रामीणों ने गांव को जोड़ने वाले निर्माणाधीन पुलों के निर्माण कार्य में तेजी लाने की मांग की। अधिकांश ग्रामीणों ने जंगली जानवरों के द्वारा कृषि खेती को नुकसान पहुंचाने व वन विभाग द्वारा गांव के नजदीक बांस रोपण न करने का अनुरोध किया गया। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी गिरीश गुणवंत, जलागम के संयुक्त निदेशक डा.एके डिमरी, कालागढ़ टाइगर रिजर्व वन प्रभाग के प्रभागीय वनाधिकारी तरुण एस., जलागम के उपनिदेशक डा.डीएस रावत, लैंसडौन वन प्रभाग के उप प्रभागीय वनाधिकारी रजत कपिल भी मौजूद रहे।

कोटद्वार की और भी खबरें पढ़ें www.jagran.com

एक जिला एक नदी के सिद्धांत पर बनाई जाएगी कार्ययोजना

जलागम सचिव दिलीप जावलकर ने सारा की बैठक में दिए निर्देश

देहरादून। सचिव जलागम व स्प्रिंग एंड रिवर रिजुविनेशन अथॉरिटी(सारा) के मुख्य कार्यकारी अधिकारी दिलीप जावलकर ने कहा कि प्राकृतिक जलस्रोतों के संरक्षण व पुनर्जीवित करने के लिए एक नदी एक जिला के सिद्धांत पर कार्ययोजना बनाई जाएगी।

बुधवार को सचिवालय में राज्य स्तरीय कार्यकारी समिति की बैठक में प्रदेशभर से जल संरक्षण व नदी पुनर्जीवन से संबंधित कार्यों की समीक्षा की गई। 24.68 करोड़ की लागत से आठ नई कार्य योजनाओं को स्वीकृति दी गई। इनमें 18.61 करोड़ की राशि सारा से आवंटित की जाएगी। सचिव ने निर्देश दिए कि प्रत्येक जिला अपनी एक प्रमुख या संकटग्रस्त नदी की पहचान कर उसके कैचमेंट एरिया में जल स्रोतों के पुनर्जीवन कार्यों को प्रभावी रूप से लागू करें। जिलास्तर पर सारा समितियों की बैठकें कर प्रस्तावों को आगामी राज्य स्तरीय बैठक में रखा जाए। जल संरक्षण कार्यों में स्थानीय समुदायों की भागीदारी हो। ग्राम पंचायत स्तर पर धारा-नौला संरक्षण समितियां गठित की जाएं। जो स्थानीय स्तर पर निगरानी करेंगी।

समितियों को सारा के माध्यम से वित्तीय व तकनीकी सहायता प्रदान की जाएगी। स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन के लिए पैरा हाइड्रोलॉजिस्टों की तैनाती की जाए। उन्होंने विभिन्न कार्य योजनाओं के तहत निर्मित आरसीसी चेक डैमों की वर्षा काल के बाद स्थिति का मूल्यांकन करने के निर्देश दिए।

अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी कहकशां नसीम ने एक करोड़ से अधिक लागत की आठ कार्ययोजनाओं का विस्तृत प्रस्तुतीकरण दिया। इसमें पौड़ी की तीन, नैनीताल की दो, चंपावत की एक और पिथौरागढ़ की दो योजनाओं की जानकारी दी। इस मौके पर संयुक्त निदेशक डॉ.एके डिमरी, परियोजना निदेशक कुमाऊं डॉ.एसके उपाध्याय, परियोजना निदेशक गढ़वाल डॉ.एनएस बर्फाल के अलावा आईआईटी रुड़की, केंद्रीय भूजल बोर्ड, वन, सिंचाई विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। ब्यूरो

जलागम और सिंचाई के कार्यों पर करें विशेष फोकस : जावलकर

गुणवत्ता के साथ समय से कार्य पूरे करने के निर्देश

अल्मोड़ा। उत्तराखंड शासन के सचिव दिलीप जावलकर ने विकास योजनाओं, कार्यक्रमों और बेस्ट प्रैक्टिसेज की समीक्षा की। उन्होंने विभागों को योजनाओं को समय से गुणवत्ता के साथ पूरा करने के निर्देश दिए।

शनिवार को हुई समीक्षा बैठक में सचिव ने आपदा प्रबंधन, सिंचाई, जलागम विकास, राजस्व सहित कई विभागों की प्रगति की जानकारी ली। उन्होंने विशेष रूप से जलागम प्रबंधन के कार्यों की समीक्षा करते हुए तेजी लाने को कहा। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) में जलागम से जुड़े कार्य अनिवार्य रूप से शामिल किए जाएं और नियमित समीक्षा के जरिए इनकी प्रगति सुनिश्चित की जाए।

उन्होंने कहा कि वनीकरण जल संरक्षण और भूमिगत जल पुनर्भरण का सबसे प्रभावी माध्यम है। इसलिए जलागम के सभी कार्यों में वनीकरण को प्राथमिकता दी जाए। सिंचाई और जल संरक्षण परियोजनाओं में नवीन तकनीकों को अपनाने पर भी बल दिया। बैठक में डीएम आलोक कुमार पांडेय, सीडीओ रामजी शरण शर्मा, उप निदेशक जलागम अजय कुमार सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। संवाद

किसानों को मिलेगा कार्बन क्रेडिट का लाभ

देहरादून। जलागम प्रबंधन विभाग ने किसानों की आय बढ़ाने के लिए कार्बन क्रेडिट मॉडल पर काम तेज करने के निर्देश दिए हैं।

सचिव जलागम दिलीप जावलकर ने मंगलवार को विभागीय समीक्षा बैठक में कृषि योग्य परती भूमि पर कृषि-औद्यानिकी और वनीकरण मॉडल विकसित कर किसानों को कार्बन क्रेडिट उपलब्ध कराने की संभावनाओं पर चर्चा की। साथ ही प्रदेशभर में ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व के नौले-धारों के पुनरोद्धार और जल संरक्षण कार्यों के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए।

ऐसी कार्ययोजनाएं बनाएं, जिनसे किसानों को मिले कार्बन क्रेडिट का लाभ

राज्य ब्यूरो, जागरण, देहरादून : देहरादून। सचिव जलागम प्रबंधन दिलीप जावलकर ने कहा कि विभाग ऐसी कार्ययोजनाएं तैयार करे, जिससे प्रदेश के अधिक से अधिक किसानों को कार्बन क्रेडिट का लाभ मिल सके। उन्होंने निर्देश दिए कि कृषि योग्य परती भूमि पर कृषि-औद्यानिकी और वनीकरण माडल विकसित करते हुए किसानों की आय बढ़ाने के विकल्पों पर प्रभावी रूप से काम किया जाए। मंगलवार को जलागम प्रबंधन विभाग की समीक्षा बैठक में अधिकारियों की प्रस्तुतियों के बाद जावलकर ने कहा कि कार्बन क्रेडिट पर कार्य कर रही एजेंसियों से प्रस्ताव आमंत्रित कर प्रदेश में इसकी संभावनाओं का विस्तृत अध्ययन किया जाए।

amarujala.com देहरादून | शनिवार, 11 अक्तूबर 2025 11

सचिव ने ग्रीन-एजी परियोजना के कार्यों का किया निरीक्षण

ग्रामीणों से संवाद कर दी परियोजना की जानकारी

संवाद न्यूज एजेंसी

दुगड्डा/कोटद्वार। दुगड्डा ब्लॉक के ग्रामसभा जमरगड्डी में शुक्रवार को जलागम प्रबंध के सचिव दिलीप जावलकर ने ग्रीन-एजी परियोजना के तहत किए जा रहे कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने ग्रामीणों से संवाद कर समस्याएं भी जानी।

सचिव दिलीप जावलकर शुक्रवार को आमसौड़ से जमरगड्डी तक खस्ताहाल जोखिम भरे मोटर मार्ग से होते हुए जमरगड्डी गांव में पहुंचे। उन्होंने ग्रीन-एजी परियोजना के तहत किसानों एवं समुदाय के सहयोग से की जा रही कृषि, बागवानी, सिंचाई, जैविक विधि से धान, मंडुवा व दलहन की खेती का निरीक्षण किया।

उन्होंने फसलों में कीट नियंत्रण के लिए सोलर ट्रैप की जानकारी भी ली। परियोजना के अति वरीयता में चयनित कुल 82 ग्रामों में मानव वन्यजीव संघर्ष, लैंटाना उन्मूलन, चेन लिंक घेरबाड़, स्थानीय प्रजाति के बीजों व नस्लों व फार्मर फील्ड स्कूल के माध्यम से कृषि को बढ़ावा देकर जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण के उद्देश्य से कार्यान्वित किया जा रहा है। उन्होंने सीडीओ गिरीश चंद्र गुणवंत को ग्रीन-एग परियोजना के बारे में आवश्यक दिशा निर्देश दिए।

ग्रामीणों ने मैदानी क्षेत्रों से बंदर पकड़कर पहाड़ के ग्रामीण क्षेत्रों में न छोड़ने, हिंसक वन्यजीवों से निजात दिलाने, ग्रामीणों के आवाजाही वाले रास्तों के निकट बांस न लगाने की मांग की। पूर्व प्रधान अनीता देवी ने सड़क निर्माण में लापरवाही बरतने की शिकायत की।

इस अवसर पर केटीआर वन प्रभाग के डीएफओ तरुण एस, जलागम योजना के संयुक्त निदेशक डॉ. एके डिमरी, उप परियोजना निदेशक डॉ. टीएस रावत, एसडीओ रजत कपिल, प्रशांत हिंदवान, बीडीओ बीडी रतूड़ी, वन क्षेत्राधिकारी उमेश चंद्र जोशी आदि मौजूद रहे।

जलागम कार्मिकों ने केन्द्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, कटक में लिया प्रशिक्षण

केन्द्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, कटक में उत्तराखण्ड जलवायु अनुकूल बारानी कृषि परियोजना के कार्मिकों के लिए 18 से 21 नवंबर 2025 तक चारदिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रशिक्षण में परियोजना के उप निदेशक, विषय विशेषज्ञ, यूनिट अधिकारी, एग्रीबिजनेस मैनेजर आदि शामिल हुए।

प्रशिक्षण कार्यक्रम का विषय “Climate Smart Agricultural Practices for Enhancing Resilience and Profitability in Rice based Cropping System" था। उद्घाटन सत्र में केन्द्रीय चावल अनुसंधान संस्थान के निदेशक डा. जीएके कुमार, प्रधान वैज्ञानिक डा. प्रताप भट्टाचार्य, वरिष्ठ वैज्ञानिक डा. संगीता मोहंती, डा. अंजनी कुमार ने प्रतिभागियों को संबोधित किया। प्रशिक्षण का उद्देश्य धान आधारित कृषि प्रणाली में जलवायु अनुकूल तकनीकों, उत्पादन वृद्धि एवं आय को बढ़ावा देना था। इसके तहत जलवायु परिवर्तन की स्थिति में धान की स्थिरता को बढ़ाना, उन्नत किस्मों, नवीन तकनीकों की जानकारी, मशीनीकरण, पोषक तत्व प्रबन्धन एवं एकीकृत कीट प्रबन्धन आदि विषयों पर जानकारी दी गई।

प्रशिक्षण में केन्द्रीय चावल अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों द्वारा पर्वतीय एवं मैदानी क्षेत्रों में कम पानी से अधिक धान की उपज के तरीकों तथा धान की सीधी बुआई की विधि के बारे में बताया गया। इसके साथ ही बदलते जलवायु परिदृश्य में एकीकृत पोषक तत्व प्रबन्धन को अपनाने, पोषक तत्वों को सही समय और सही मात्रा में देने संबंधी जानकारी दी गई। उत्तराखण्ड के लिए उपयुक्त धान की किस्मों- पंत सुगन्ध धान 25, पंत धान 23, पंत सुगन्ध धान-15, 17, 21, 25, 27, पंत बासमती-1, 2 आदि किस्मों के विषय में भी बताया गया।

प्रशिक्षण में बताया गया कि धान की सीधी बुआई में प्रभावी सिंचाई प्रबन्धन, उच्च पैदावार बनाये रखने हेतु जल उपयोग को अनुकूलित करने के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है। यह उन क्षेत्रों के लिए अधिक फायदेमंद है, जहां पानी की कमी है और भूजल पंपिंग की लागत अधिक आती है। प्रशिक्षण के दौरान कृषि विज्ञान केन्द्र संथापुर तथा केन्द्रीय चावल अनुसंधान संस्थान द्वारा गोद लिए गए गांवों का दौरा भी करवाया गया।

जलागम दर्पण- वर्ष 11, अंक 04, अक्टूबर-दिसम्बर 2025

संरक्षक- दिलीप जावलकर, मुख्य परियोजना निदेशक

संपादक मंडल
हिमांशु खुराना, परियोजना निदेशक
कहकशां नसीम, परियोजना निदेशक
डा. ए.के. डिमरी, संयुक्त निदेशक
डा. डी.एस. रावत, उप परियोजना निदेशक
डा. मीनाक्षी जोशी, उप परियोजना निदेशक
मनीष ओली, नॉलेज मैनेजमेंट एक्सपर्ट

हमारा पता
जलागम दर्पण
जलागम प्रबन्ध निदेशालय
इन्दिरानगर, फॉरेस्ट कालोनी
देहरादून, उत्तराखण्ड

Email: wmd-ua@nic.in Website: www.wmduk.gov.in